राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, रविवार, 28 जून 2026
वर्ष 14, अंक 80, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है, इसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है...03

ईरान ने सीजफायर का किया उल्लंघन,...04

ना ट्रस्ट पर ट्रस्ट, ना एफआईआर पर भरोसा... चंदा चोरी केस ने खड़े किए सवाल, संतों में भी आक्रोश

● राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे ट्रस्ट, एस आई टीऔर एफआईआर की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. बैंक अधिकारी और ट्रस्ट पदाधिकारी जांच के घेरे में हैं

● चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि हुई है, जिस पर 11 जुलाई को फैसला होगा. धीरेंद्र शास्त्री सहित संतों और विपक्षी नेताओं ने भी इस हेराफेरी पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिससे यह मामला गहरा गया है

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर रोज नए राज, नए आरोप और नए सवाल सामने आ रहे हैं. सबसे चिंता की बात ये है कि मंदिर के ट्रस्ट पर, एस आई टी की जांच पर और दर्ज एफ.आई.आर. पर भी सवाल उठ रहे हैं. ट्रस्ट पर किसी को अब ट्रस्ट नहीं रह गया है. वैसे जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है. अभियुक्तों से पूछताछ हो रही है. नई जानकारी सामने आ रही है. लेटेस्ट जानकारी के अनुसार बैंक के अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी जांच के दायरे में हैं.

वहीं, चढ़ावा चोरी के पर्दाफाश के दो हफ्ते बाद एफ.आई.आर. दर्ज होती है. सवाल तो इस पर है कि उस एफ.आई.आर. की जानकारी भी अधूरी है तो बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कैसे होगी ये भी पूछा जा रहा है. आज चंपत राय के इस्तीफे की पुष्टि हुई है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने इस्तीफे की पुष्टि की है. राम मंदिर ट्रस्ट ने लिखित बयान जारी कर ये बताया है है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिला है. हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है.

11 जुलाई को चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला

11 जुलाई को होने वाली बैठक में इस्तीफे पर फैसला होगा. लिखित बयान में ये संदेश दिया गया है कि निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण जांच और रामभक्तों का विश्वास बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं. न्यास उन सभी श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं सौंपी थी. वे सभी सुरक्षित हैं उनका पूरा लेखा-जोखा उपलब्ध है. सभी श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा भ्रामक और निराधार अफवाहों से बचने की सलाह भी दी गई है.

चंदा चोरी केस से संत भी खफा

इसमें कोई शक नहीं है चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठे हैं. यहां तक कि कई संत भी इसका विरोध कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी सनातनी चेतावनी भी दी है. बात सिर्फ पंडित धीरेंद्र शास्त्री की नहीं है. जबसे ये मामला सामने आया है. कई संत सवाल उठा रहे हैं. चेतावनी दे रहे हैं. सच सामने लाने की बात कह रहे हैं. इतना ही नहीं एस आई टी जांच, एफ आई आर और

कार्रवाई पर उन्हें भरोसा नहीं है. ये कहा जा रहा है कि मंदिरों में दखल खत्म होना चाहिए. नैतिकता तब होती जब चोरी साबित होने पर इस्तीफा दिया जाता

राम मंदिर चढ़ावा में हेराफेरी वाले आरोपों और जांच के बीच पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आक्रामक बयान दिया है या फिर ये कहें कि सनातनी चेतावनी दी है.हाल में ही इंडोनेशिया के जकार्ता में एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने चढ़ावा चोरी करने वालों की तुलना रावण से की. ये कहा कि रावण ने तो माता सीता का हरण किया था. यहां आस्था और भरोसे का हरण हुआ है.

बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे में

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में प्रत्येक दिन नई जानकारी सामने आ रही है. ये पता चला है कैसे कैश की हेराफेरी होती थी. सूत्रों के अनुसार जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार जांच के दायरे में कुछ बैंक अधिकारी और कर्मचारी हैं. ये दावा किया गया है कि कुछ बैंक कर्मचारियों को नियमित हिस्सा दिया जा रहा था. मतलब सुनियोजित साजिश की तरह नेटवर्क बनाकर चोरी की जा रही थी. बताया तो ये भी जा रहा है कि कई बार बैंक कर्मचारियों ने भी नकदी में हेरफेर की.

एस आई टी उन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है. इतना ही नहीं पूरे मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है. कुछ पदाधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है. ये पता किया जा रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े कौन कौन पदाधिकारी थे जो इन लोगों से मिले हुए थे. यह सवाल है कि मामले की जांच कैसे की जा रही है...दो स्तरों जांच चल रही है.

पहला ये कि पुलिस जांच के जरिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं

दूसरा ये है कि एस आई टी पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल कर रही है. संबंधित लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं

एफआईआर को लेकर भी सवाल

हालांकि एफआईआर को लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं. नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं. एस आई टी की जांच के दो हफ्ते बाद एफ.आई.आर. को दर्ज हुई, लेकिन क्या ये सख्त कार्रवाई के लिए काफी है. आइए जानें क्यों एफ.आई.आर. सवालों में है.

एफआईआर में नामजद कर्मचारियों के माता-पिता का नाम और उनका पता नहीं है.मतलब ये कि जानकारी अधूरी है।

बंगाल में ईसीएल का बुलडोजर एक्शन, अवैध टीएमसी कार्यालय किया जमींदोज

● ईसीएल ने तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया के कथित कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है

कंपनी की जमीन पर बने इस 'अवैध निर्माण' को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया. इस घटना से इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है

ईसीएल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया के कथित कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया. इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि ईसीएल की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन और ईसीएल की टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंची. इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया

कार्रवाई के दौरान चपुई कोलियारी के ॥क्रसोमू तिवारी और रानीगंज थाना अंतर्गत नीमचा फाड़ी की पुलिस उपस्थिति में टीएमसी कार्यालय के अंदर मौजूद फर्नीचर, सोफा और टेबल साथ लेकर चले गये. इसके बाद बुलडोजर ने भवन को जमींदोज कर दिया. कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए

टीएमसी नेता के अवैध कार्यालय पर चला बुलडोजर

स्थानीय भाजपा नेता संजय रुईदास के अनुसार यह कार्यालय लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया से जुड़ा हुआ था. ईसीएल अधिकारियों का कहना है कि कंपनी की जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

फिलहाल ईसीएल की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ से लेता है।

बुलडोजर एक्शन से हड़कंप

हालांकि यह कार्यालय पिछले काफी दिनों से विवादों में था. कुछ दिन पहले यहां विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी. उस समय परिसर से कुछ दस्तावेज एवं मतदाता पहचान पत्र मिलने की खबरें आई थी, हालांकि बाद में इसकी पुष्टि नहीं हुई.

हालांकि बुलडोजर एक्शन के दौरान विनोद नोनिया कहीं नजर नहीं आए और न ही इस मामले में उनका रिएक्शन ही सामने आया है. वहीं स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई है कि यदि वास्तव में यह निर्माण ईसीएल की जमीन पर थी, तो इतने सालों तक इसे हटाने का प्रयास क्यों नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की।

जमीन की बंदोबस्ती पर बहस तेज

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में एक नयी बहस छिड़ गयी है. स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि निर्माण वास्तव में ईसीएल की जमीन पर था, तो इतने वर्षों तक इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. कई सामाजिक संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की मांग की है. फिलहाल ईसीएल की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसके राजनीतिक प्रभावों पर भी सुगबुगाहट तेज है।

संक्षिप्त ख़बरें

विधवा महिला पर समधी बना रहा कोर्ट मैरिज का दबाव, परेशान होकर आगरा पुलिस कमिश्नर से लगाई मदद की गुहार

अछनेरा (आगरा)। अछनेरा थाना के बड़ी बस्ती जाटवान निवासी एक विधवा महिला ओमवती देवी ने अपने समधी जगदीश शास्त्रीपुरम सिकंदरा पर जबरन कोर्ट मैरिज का दबाव बनाने, अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी दिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2025 में उसने अपनी दोनों बेटियों का विवाह आगरा निवासी जगदीश के पुत्रों से किया था। आरोप है कि शादी के बाद से समधी उस पर गलत नीयत रखता है। मकान बेचकर उसके साथ रहने व कोर्ट मैरिज करने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर बेटियों का जीवन बर्बाद करने की धमकी दी गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि समधी की बेटियां भी मोबाइल पर धमकी दे रही हैं। पीड़िता ने अपनी और बेटियों की सुरक्षा की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच पुलिस स्तर पर लंबित है

PNB की भदरौली शाखा में सीबीआइ का छापा, रातभर खंगाले दस्तावेज

आगरा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की जैतपुर के भदरौली बैंक शाखा में गुरुवार शाम को सीबीआइ की टीम ने छापा मारा। गाजियाबाद से पहुंची 12 सदस्यीय टीम ने बैंक के दस्तावेजों को खंगालने के साथ ही स्टाफ से कई घंटे तक पूछताछ की। शुक्रवार सुबह तक सीबीआइ की टीम ने बैंक में जांच पूरी की। कार्रवाई 16 घंटे तक चली। बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। छापा क्यों मारा गया? सीबीआइ ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। चर्चा है कि सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी में वित्तीय अनियमितता की जांच की गई। सीबीआइ की 12 सदस्यीय टीम गाजियाबाद से गुरुवार शाम चार बजे पीएनबी की भदरौली शाखा पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से थाना पुलिस को बुलाकर बैंक के बाहर तैनात किया गया।

निर्दोष ने दुष्कर्म में काटी पांच साल जेल, पीड़िता की मां ने कोर्ट में बताया सच

● पीड़िता की मां ने बयान देकर कहा कि अपराध करने वाला यह नहीं कोई और है

● सबूतों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने युवक को बरी कर दिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर ग्रामीण। दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को पांच साल तक जेल में बंद रहना पड़ा, जबकि यह अपराध उसने नहीं किया था, पीड़िता की मां ने बयान देकर कहा कि अपराध करने वाला यह नहीं कोई और है, सबूतों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने युवक को बरी कर दिया, साथ ही लापरवाही पर विवेचक और पर्यवेक्षण अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजा हैं कमिश्नरेट अंतर्गत थाना बिधनू क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण जयंती विहार की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को 25 मई 2021 को विक्की नामक युवक ने पकड़ कर झाड़ियों में ले गया था और पीटकर रूपए छीन लिए, पीड़िता ने घर पहुंचकर पिता को बताया तों उन्होंने बिधनू थाने में विक्की के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाकर पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। विवेचना बिधनू थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने की,,इस दौरान अपराध करने वाला विक्की फरार हो गया,,तो विवेचक ने गुड वर्क दिखाने के चक्कर में कैंट में रहने वाले अमीन लायल को विक्की बना कर जेल भेज दिया। पीड़िता से तस्दीक भी नहीं कराया,, अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके पिता समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपी के पिता और मां ने बयान दर्ज कराए। पीड़िता और उसके माता-पिता ने कोर्ट में कहा कि अपराध करने वाला विक्की उसके पड़ोस में रहता था। शादीशुदा था।

घटना के बाद वह भाग गया था,, कुछ दिन बाद उसके बीवी बच्चे भी घर छोड़ कर चले गए थे। अमीन ने कोई अपराध नहीं किया हैं, पुलिस ने अमीन को गलत जेल भेजा। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमीन लायल,उप नाम विक्की को दोषमुक्त करार दिया। पीड़ित मां ने

बताया कि बेटी के साथ मारपीट हुई थी,रूपय छीने गए थे, लेकिन दुष्कर्म नहीं हुआ था। अपराध करने वाला विक्की उसके पड़ोस में रहता था,35/40 साल के लगभग था, उसके बच्चे भी थे कठघरे में खड़े अमीन को देख कर कहा कि यह विक्की नही है,और इसने मेरी बेटी के साथ कोई अपराध नही किया है,, वहीं अमीन के पिता ने बयान में कहा कि घटना वाले दिन बेटा वनारस गया था। टिकट भी विवेचक को दिया था लेकिन उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। जिरह में विवेचक ने भी माना कि गिरफ्तारी के समय आरोपी की शिनाख्त पीड़िता व वादी से नही कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह की आंतरिक व बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। और नह दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी इन सभी से दुष्कर्म की घटना संदेहास्पद बन गई थी।

रास्ता रोक महिला से गाली-गलौज

ललितपुर। थाना नाराहट क्षेत्र में एक महिला और उसके पुत्र का रास्ता रोककर गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर हुई बताई जा रही है। पीड़िता ने आरोपियों के डर और दबाव के कारण तत्काल शिकायत नहीं की। घटना के 23 दिन बाद थाने पहुंचकर दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाराहट के ग्राम बनियाना निवासी कौशल्यारानी पत्नी फूलचन्द्र ने बताया कि 2 जून 2026 को शाम करीब 5 बजे वह नाराहट स्थित बैंक से काम निपटाकर अपने पुत्र रौशन के साथ टीकमगढ़ जा रही थीं। रास्ते में मकरीपुर गांव से पहले स्थित भूसा की टाल के पास गांव के ही कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि नातीराजा एवं क्षेत्रपाल राजा पुत्रगण गजेंद्र राजा तथा रानाराजा एवं नरेंद्र राजा पुत्रगण कल्लू राजा ने पुरानी मुकदमेबाजी को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने मां-बेटे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए।

मुख्यमंत्री ने देवरिया को दी 456 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

● सोनूघाट-बरहज फोरलेन का शिलान्यास, बरहज को जलमार्ग से जोड़ने की घोषणा

देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बरांव में आयोजित जनसभा के दौरान बरहज और रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए ?456.38 करोड़ की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें ?64.94 करोड़ की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा ?391.44 करोड़ की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया महर्षि देवराहा बाबा और बाबा राघवदास की पावन कर्मभूमि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, पुल और आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में सोनूघाट से बरहज तक लगभग ?172 करोड़ की लागत से बनने वाली फोरलेन सड़क का शिलान्यास किया गया। साथ ही बरहज को जलमार्ग से जोड़ने की भी घोषणा की, जिससे स्थानीय व्यापार को नया विस्तार मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून-व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने युवाओं को रोजगार, किसानों को आधुनिक सुविधाएं और गरीबों को आवास, आयुष्मान कार्ड, बिजली तथा पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अपनाने की भी अपील की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण-पत्र वितरित किए। जनसभा से पहले उन्होंने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी भाग लिया। सभा को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भी संबोधित किया। उन्होंने सरकार की विकास योजनाओं, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आवास, सड़क, बिजली और किसान हितैषी कार्यक्रमों को प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही।

जनपद बाराबंकी में सिरौली गूंग व अन्य ग्राम समूहों की बाढ़ से हुआ बचाव

लखनऊः उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में बहने वाली घाघरा नदी वर्षों से तीव्र कटान, बाढ़ तथा अनियमित जल प्रवाह के कारण आसपास के ग्रामों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई थी। विशेष रूप से ग्राम सिरौली गूंग एवं अन्य ग्राम समूह प्रतिवर्ष बाढ़ एवं कटान से प्रभावित होते रहे। किसानों की कृषि भूमि कट रही थी तथा ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का वातावरण बना रहता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2024 में इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु चौनेलाइजेशन द्वारा रिवर टेऊनिंग कार्य की परियोजना तैयार कराई और बाढ़ से कटान की सुरक्षा के लिए परियोजना बनवाकर कार्य शुरू कराया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी के दबाव को नियंत्रित कर गांवों, कृषि भूमि एवं तटबंधों को सुरक्षित करना था। जून 2025 में यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई और आज यह क्षेत्रीय सुरक्षा एवं तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट निर्माण कार्य बन चुकी है।

पूर्व में घाघरा नदी की मुख्य धारा लगातार गांवों की ओर बढ़ रही थी। लगभग 12,000 की आबादी एवं 1600 घर बाढ़ और कटान से प्रभावित हो रहे थे। कृषि भूमि का लगातार कटाव हो रहा था तथा कई परिवारों के सामने विस्थापन का संकट उत्पन्न हो गया था। इस समस्या के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ड्रोन सर्वेक्षण एवं तकनीकी अध्ययन के माध्यम से अत्यधिक कटान की पुष्टि की गई। इसके उपरांत प्रशासन एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कार्य योजना तैयार कर बाढ़ बचाव का कार्य किया। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के दबाव को प्रभावित ग्रामों से हटाकर नियंत्रित चौनल की ओर मोड़ना था। इसके अंतर्गत लगभग 3.8 किलोमीटर लंबाई एवं 45 मीटर चौड़ाई में चौनल निर्माण का कार्य किया गया। ड्रेजिंग कार्य हेतु अत्याधुनिक ड्रेजर मशीन, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर तथा मड पम्प का उपयोग किया गया। नदी की मुख्य धारा को सुरक्षित दिशा में मोड़ने के लिए जियोट्यूब एवं बल्ली पाइलिंग का उपयोग किया गया। ड्रेजिंग कार्य पूर्ण होने के बाद जियोट्यूब आधारित संरचनाओं द्वारा तटबंधों को मजबूत किया गया, जिससे नदी के दबाव को नियंत्रित करने एवं कृषि भूमि को कटान से सुरक्षित रखने में सहायता मिली।

परियोजना को नेशनल फ्रेमवर्क फॉर रिवर सेडिमेंट मैनेजमेंट-2022 एवं नियमों के अनुरूप पूर्ण किया गया है। घाघरा जैसी विशाल एवं तीव्र प्रवाह वाली नदी में कार्य करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। बदलते जलस्तर, मौसम संबंधी कठिनाइयों एवं तीव्र धारा के बावजूद परियोजना टीम ने निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया। परियोजना के दौरान अत्याधुनिक ड्रेजर मशीनों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप चौनल की गहराई एवं चौड़ाई सुनिश्चित की गई। इस परियोजना के पूर्ण होने से 12000 की आबादी और 1600 से अधिक घर लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही 4500 हेक्टेयर की खेतिहर भूमि सुरक्षित हुई है। इस परियोजना से जन-धन की हानि में कमी आई है तथा कृषि भूमि भी सुरक्षित हुई है।

जून 2025 में यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण कर दी गई। मानसून के दौरान नदी की मुख्य धारा नियंत्रित चौनल में प्रवाहित हुई तथा कटान की गति में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। ग्रामीणों ने पहली बार राहत एवं सुरक्षा का अनुभव किया। वर्षों से बाढ़ एवं कटान से प्रभावित क्षेत्र अब अधिक सुरक्षित दिखाई देने लगे हैं। इसके निर्माण से कटान की समस्या में

उल्लेखनीय कमी आई, तटबंधों की मजबूती में वृद्धि हुई, कृषि भूमि एवं गांवों की सुरक्षा, नदी के प्रवाह मार्ग में सुधार आया, जल निकासी क्षमता में वृद्धि हुई और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना विकसित हुई है। जनपद बाराबंकी में सिरौली गूंग एवं अन्य ग्राम समूहों की सुरक्षा हेतु संचालित चौनेलाइजेशन द्वारा रिवर ट्रेनिंग कार्य की परियोजना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीणों के जीवन, कृषि भूमि एवं भविष्य को सुरक्षित करने वाली ऐतिहासिक पहल सिद्ध हुई है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित यह परियोजना भविष्य में बाढ़ एवं कटान प्रबंधन की दिशा में प्रेरणादायक मॉडल के रूप में कार्य करेगी।

अभिषेक सिंह

सीतापुर में घटिया निर्माण पर ठेकेदार को नोटिस, कार्य न करने पर जब्त होगी जमा धनराशि

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिधौली (सीतापुर)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत नगर पंचायत सिधौली में कराए जा रहे आरसीसी रोड व नाली निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग पर नगर पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। समय पर कार्य पूरा न करने और निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल करने पर मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।

12 लाख की लागत, फिर भी काम अधूरा

वार्ड गांधीनगर दक्षिणी में हबीब के मकान से राघव मिश्रा के मकान तक आरसीसी रोड व नाली का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए आमंत्रित निविदा में मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी की दरें सर्वन्यून थीं। इसी आधार पर कंपनी को 29 फरवरी 2024 को लगभग 12 लाख रुपये

की लागत से कार्यादेश जारी किया गया था।

जेई की जांच में खुली पोल

नगर पंचायत के अवर अभियंता नवीन कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया तो निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। साथ ही दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है।जांच में यह भी सामने आया कि टेंडर मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम है, लेकिन मौके पर काम जवान सिंह कराते मिले।

महराजगंज में सरकारी सुविधाओं से संवरी ग्रामीण महिलाओं की तकदीर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आज प्रदेश के गांवों में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे मजबूत माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वयं सहायता समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से पूर्वांचल के सीमावर्ती जनपद महराजगंज ने इस दिशा में शासन की मंशानुरूप उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर महिला सशक्तिकरण की एक नई और प्रेरक मिसाल देश-प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। महराजगंज में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने बैंक क्रेडिट लिंकेज और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एनआरएलएम के अंतर्गत जिले में 5684 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 130.12 प्रतिशत है।

यह अभूतपूर्व उपलब्धि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर अत्यंत प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं तथा ग्रामीण महिलाएं आर्थिक प्रगति की नई इबारत लिख रही हैं। सरकार की इन दूरदर्शी योजनाओं से आज उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को केवल वित्तीय बचत और पारंपरिक दायरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें स्वरोजगार, कौशल विकास, आधुनिक बैंकिंग सुविधा, सुदृढ़ विपणन और तकनीकी सहायता से जोड़कर समग्र विकास का एक अनूठा मॉडल तैयार किया है। महराजगंज जनपद में इसके क्रांतिकारी परिणाम देखने को मिल रहे हैं। समूहों को समयबद्ध तरीके से बैंक ऋण और रिवॉल्विंग फंड मिलने से महिलाओं ने अनेक नवीन व स्वरोजगार आधारित सूक्ष्म उद्योग प्रारंभ किए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं केवल पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आधुनिक सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, अचार-मुरब्बा उत्पादन, पापड़-बड़ी निर्माण, डेयरी उद्योग, उन्नत बकरी पालन, मुर्गी पालन, वैज्ञानिक पद्धति से सब्जी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा निर्माण, हस्तशिल्प, सौंदर्य उत्पाद निर्माण और ऑर्गेनिक खेती जैसे विविधीकृत एवं तकनीकी क्षेत्रों में पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं।

इससे न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि गांवों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिली है। इस पूरे तंत्र की सबसे बड़ी सफलता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में छोटे-छोटे उत्पादन केंद्र स्थापित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और रोजगार के लिए होने वाले पलायन में भारी कमी आई है। पूर्व में ग्रामीण महिलाएं आर्थिक संसाधनों की भारी कमी, बैंकिंग प्रणाली की जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाती थीं। परंतु आज प्रदेश सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं और जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से वही महिलाएं संगठित होकर समूह बना रही हैं, बैंकों से संस्थागत ऋण ले रही हैं, बड़े पैमाने पर व्यवसाय चला रही हैं और समाज की अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

सरकार द्वारा संचालित 'लखपति दीदी' अभियान ने ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। महराजगंज जनपद में अब तक 50,179 महिलाएं विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों से जुड़कर 'लखपति दीदी' बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा ग्रामीण समाज में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और उनकी मजबूत होती स्थिति का प्रत्यक्ष संकेत है। जनपद के मिठौरा विकासखंड में सर्वाधिक 6644 महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, जबकि फरेंदा विकासखंड में 6375 महिलाएं इस गौरवशाली श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। ये प्रगतिशील आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यदि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में हो और प्रशासन का निरंतर सहयोग मिले, तो ग्रामीण महिलाएं हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला समूहों को आधुनिक कृषि और पशुपालन से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया है। इसी क्रम में महराजगंज में 548 कृषि सखियों और पशु सखियों का एक विशेष कार्यबल तैयार किया गया है। ये प्रशिक्षित महिलाएं गांव-गांव जाकर समूहों से जुड़ी अन्य दीदियों को उन्नत खेती, जैविक कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और आय बढ़ाने के आधुनिक वैज्ञानिक उपाय सिखा रही हैं।

इस अभिनव पहल से महिलाओं को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने, कृषि लागत घटाने और कुल उत्पादन बढ़ाने में अभूतपूर्व मदद मिल रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत हुआ है। इसके साथ ही, महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की निर्बाध बिक्री सुनिश्चित करना भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद में 'शी मार्ट' और 'प्रेरणा कैंटीन' जैसे विशिष्ट प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं जो समूहों के उत्पादों को एक स्थायी बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। इन मंचों के माध्यम से समूहों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ, उत्कृष्ट हस्तशिल्प और घरेलू उपयोग की वस्तुएं स्थानीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रही हैं। तकनीक के इस दौर में महिला उद्यमिता को नई उड़ान देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे कई समूह ऑनलाइन ऑर्डर लेकर सीधे देश भर के ग्राहकों तक अपने उत्पाद पहुंचा रहे हैं। डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के जरिए महिलाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मार्केटिंग के गुर सीख रही हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो गई है।

स्वयं सहायता समूह मॉडल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता यह है कि ग्रामीण महिलाएं अब स्थानीय साहूकारों के चंगुल और उनके शोषण से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। पहले छोटी-मोटी पारिवारिक जरूरतों के लिए भी उन्हें ऊंचे ब्याज पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिससे ग्रामीण परिवार कर्ज के दलदल में फंस जाते थे। अब समूहों के माध्यम से महिलाएं नियमित बचत कर रही हैं, स्वयं बैंक खातों का संचालन कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर बेहद सस्ती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त कर रही हैं। इस बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव ने महिलाओं में अद्भुत वित्तीय अनुशासन, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म दिया है। ऋण वापसी का उनका शत-प्रतिशत बेहतर रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाएं अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभा रही हैं।

महराजगंज की इस अनुकरणीय सफलता में शासन की नीतियों और जिला प्रशासन के कुशल समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशासन ने समूहों को बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से धरातल पर सशक्त किया है। प्रशासन और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के आपसी तालमेल से समूहों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे महराजगंज ने लक्ष्य से अधिक क्रेडिट लिंकिंग कर प्रदेश में शीर्ष स्थान बनाया। शासकीय व प्रशासनिक आयोजनों में भी समूहों के उत्पादों को वरीयता दी जा रही है, जिससे उनके स्वाभिमान को नया बल मिला है। राज्य सरकार की 'मिशन शक्ति' पहल ने ग्रामीण महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया है। आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ-साथ अब ये महिलाएं सामाजिक निर्णयों, पंचायत बैठकों और विकास कार्यों की निगरानी में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जिससे लैंगिक समानता की दिशा में एक बेहद सकारात्मक संदेश गया है।

बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में भी व्यापक सुधार देखा जा रहा है। कई समूहों ने तो अपने विशिष्ट ब्रांड नाम से उत्पाद बाजार में उतारे हैं, जो अपनी उत्कृष्ट पैकेजिंग और गुणवत्ता के कारण ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं।

सरकार का संकल्प है कि आने वाले समय में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला उद्यमी नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय हो। प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और विपणन की व्यवस्था को लगातार और सुदृढ़ किया जा रहा है। महराजगंज की यह स्वर्णिम सफलता इस बात का उद्घोष है कि जब देश की आधी आबादी को समान अवसर, आधुनिक सुविधाएं और सम्मान मिलता है, तो वे परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों की दशा और दिशा बदल देती हैं। स्वयं सहायता समूहों का यह बढ़ता कारवां 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की संकल्पना को धरातल पर साकार करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक बेहद मजबूत नींव रख रहा है।

जनपद महराजगंज

राम मंदिर चढ़ावा चोरी- आस्था पर लगा दाग और सवालों के घेरे में सिस्टम

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी ने सिर्फ पैसे की हेराफेरी का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा हमला है। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 8 लोगों के खिलाफ पहली FIR दर्ज कराई है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है इन चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर आंदोलन के बाद से अब तक पूरे देश के हिंदुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। लेकिन FIR के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। बल्कि नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हुआ था?

सीसीटीवी में साफ दिखा कि मंदिर के दानपात्रों से निकली नकदी की गिनती करने वाले कर्मचारी ही चोरी कर रहे थे। आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे शामिल हैं। इनमें से छह कैशियर हैं। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग इंचार्ज था। टिन्नू यादव का काम कैश की गिनती सुपरवाइज़ करके बैंक तक ले जाना था। यानी जिन पर भरोसा था, वही बेईमान निकले। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि 14,500 रुपए महीने की नौकरी करने वाले कर्मचारियों ने 5 साल में करोड़ों की संपत्ति बना ली। एक ने डेढ़ करोड़ की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख का प्लॉट लिया। शुरुआती अनुमान 200 करोड़ के घोटाले का है। एफआईआर दर्ज हुई, पर देर से क्यों? ट्रस्ट ने चोरी की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी बनवाई। 25 जून को एफआईआर हुई। यानी 12 दिन लग गए। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले भी दो कर्मचारियों को गुपचुप तरीके से पकड़ा गया था। बिना एफआईआर के ही रिकवरी की जा रही थी। पुलिस ट्रस्ट के साथ मिलकर पूछताछ कर रही थी।

सवाल ये है: जब चोरी का शक था तो तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? क्या ट्रस्ट पहले अपने स्तर पर मामला दबाना चाहता था? बड़े नाम गायब क्यों हैं? एफआईआर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम नहीं है। लेकिन उनका ड्राइवर टिन्नू यादव आरोपी है। विपक्ष का आरोप है कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5) और 61 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें उम्रकैद तक की सजा है। अगर टिन्नू यादव चोरी कर रहा था तो क्या चंपत राय को पता नहीं चला? या उन्होंने आंखें बंद कर लीं? एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट आने तक ये सवाल बना रहेगा। सिस्टम में खामी कहां थी? मंदिर के चढ़ावे की गिनती तीन स्तर पर होती हैः 24 प्राइवेट कर्मचारी नोट गिनते हैं। 12 ट्रस्ट कर्मचारी निगरानी करते हैं। 14 SBI और TCS के ऑडिटर होते हैं। इतनी लेयर के बावजूद चोरी हो गई। जांच में सामने आया कि एक पदाधिकारी ने कैमरे लगाने का विरोध किया था। यानी सिस्टम में पारदर्शिता की कमी थी। CCTV थे, पर निगरानी नहीं थी। ऑडिट था, पर भरोसा अंधा था। आगे क्या होना चाहिए? पहला, एसआईटी की जांच सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित न रहे। पूरी चेन की जांच हो। किसके इशारे पर चोरी हुई, पैसा कहां गया, ये साफ होना चाहिए। CM योगी ने कहा है कि 'दूध का दूध, पानी का पानी' होगा। जनता यही उम्मीद कर रही है।

दूसरा, ट्रस्ट को अपनी वित्तीय व्यवस्था सार्वजनिक करनी होगी। हर महीने कितना चढ़ावा आया, कहां खर्च हुआ, इसका डिजिटल डिस्प्ले मंदिर परिसर में लगे। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह रियल टाइम अपडेट सिस्टम बने। तीसरा, कैश हैंडलिंग खत्म हो। क्यूआरकोड, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जितना कैश कम होगा, चोरी की गुंजाइश उतनी कम होगी। चौथा, ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधि बढ़ाए जाएं। अभी सिर्फ एक आईएएस अधिकारी है। CAG से सालाना ऑडिट अनिवार्य हो। राम मंदिर सिर्फ ईंट-पत्थर की इमारत नहीं है।

ये 500 साल के संघर्ष के बाद मिली आस्था की जीत है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो भाव देश ने देखा, वो अनमोल है। अगर चंद लोग उस आस्था को कैश कराने लगेंगे तो मंदिर का मतलब खत्म हो जाएगा। FIR पहली कार्रवाई है, आखिरी नहीं। असली इम्तहान अब शुरू हुआ है - क्या ट्रस्ट दोषियों को सजा दिला पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो? क्या व्यवस्था बदलेगी ताकि फिर कोई टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा आस्था का सौदा न कर सके? जनता देख रही है। राम देख रहे हैं। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और लोगों के सवाल तब ही शांत होंगे जब इस पूरे मामले पय ठीक ढंग से पर्दा उठेगा। फिलहाल उम्मीद है कि जांच सही दिशा में हो रही है।

सनातन संस्कार और संस्कृति को आहत करती राम मंदिर में दान संबंधी कथित अनियमितताएँ

भारत की सनातन संस्कृति केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, ईमानदारी, त्याग, सेवा, उत्तरदायित्व और लोककल्याण जैसे उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन-दर्शन है। इसी कारण सनातन परंपरा के मंदिर और आश्रम सदैव केवल आस्था के केंद्र नहीं रहे, बल्कि समाज में नैतिकता, शिक्षा, सेवा और सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणास्रोत भी रहे हैं। ऐसे में यदि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या के श्रीराम मंदिर से जुड़े दान अथवा वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक या कानूनी विषय नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा से भी जुड़ जाता है। वस्तुतः किसी भी धार्मिक संस्था पर वित्तीय अनियमितता का आरोप उसके अनुयायियों को स्वाभाविक रूप से व्यथित करता है।

अयोध्या का श्रीराम मंदिर सदियों के संघर्ष, असंख्य बलिदानों और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता, मर्यादा, न्याय और आत्मसम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब मंदिर में प्राप्त दान, चढ़ावे अथवा अन्य संसाधनों के प्रबंधन में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या गबन जैसी आशंकाएँ व्यक्त होती हैं, तो समाज में चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सनातन परंपरा में दान को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धापूर्वक दिया गया दान धर्म, पुण्य और लोककल्याण का साधन बनता है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान करता है, तो वह किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि ईश्वर को समर्पित करता है। उसकी स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उस धन का उपयोग मंदिर के संरक्षण, व्यवस्था, धार्मिक गतिविधियों, सेवा कार्यों और समाज हित में पूर्ण ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। इसलिए यदि उसके दुरुपयोग की आशंका भी उत्पन्न होती है, तो वह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि श्रद्धा पर भी आघात होती है।

ऐसी घटनाओं का एक गंभीर दुष्परिणाम यह भी होता है कि समाज का एक वर्ग धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाने लगता है। दूसरी ओर, सनातन परंपरा के विरोधी तत्व कुछ व्यक्तियों की संभावित गलतियों को आधार बनाकर पूरे हिंदू समाज, उसकी धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक परंपरा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल अनुचित है, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करता है।

यह समझना आवश्यक है कि किसी संस्था में यदि कुछ व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करते हैं, तो उसका दोष पूरे धर्म, संस्कृति या करोड़ों श्रद्धालुओं पर नहीं थोपा जा सकता। जिस प्रकार किसी अस्पताल में भ्रष्टाचार होने से चिकित्सा विज्ञान दोषी नहीं हो जाता, उसी प्रकार किसी मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगने से सनातन धर्म या उसकी संस्कृति दोषी नहीं हो जाती। उत्तरदायित्व केवल उन व्यक्तियों का होता है जिन्होंने अनियमितता की है। अतः निष्पक्ष जांच के आधार पर दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं में जनता का विश्वास तभी बना रहेगा जब कानून के समक्ष किसी व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, जाति या राजनीतिक संबंध कोई संरक्षण न बन सके। वास्तव में सनातन संस्कृति स्वयं भ्रष्टाचार, छल और बेईमानी का विरोध करती है। भगवान श्रीराम का संपूर्ण जीवन सत्य, मर्यादा, न्याय और उत्तरदायित्व का आदर्श है। यदि कोई व्यक्ति श्रीराम के नाम पर प्राप्त दान का दुरुपयोग करता है, तो वह केवल कानून का ही नहीं, बल्कि श्रीराम के आदर्शों का भी उल्लंघन करता है। इसलिए निष्पक्ष जांच, पूर्ण पारदर्शिता और दोषियों पर कठोर कार्रवाई ही वास्तविक धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य है।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि सभी धार्मिक संस्थाएँ आधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अपनाएँ। डिजिटल लेखा-जोखा, नियमित स्वतंत्र ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन दान प्रणाली, सार्वजनिक आय-व्यय विवरण तथा उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएँ न केवल पारदर्शिता बढ़ाएँगी, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को भी और अधिक सुदृढ़ करेंगी। धर्म की रक्षा केवल पूजा-अर्चना से नहीं, बल्कि ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्थाओं से भी होती है। अंततः मंदिरों की पवित्रता केवल उनके भव्य भवनों या स्थापत्य में नहीं, बल्कि उनके संचालन की नैतिकता और पारदर्शिता में निहित होती है। यदि कहीं किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि कुछ व्यक्तियों के कथित कृत्यों के आधार पर संपूर्ण सनातन संस्कृति, भगवान श्रीराम की मर्यादा अथवा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को कटघरे में न खड़ा किया जाए। सत्य, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय—यही वे आधार हैं जिन पर मंदिरों की गरिमा और सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा सदैव अक्षुण्ण रह सकती है।

प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश

पत्नी-बच्चों संग तिरुपति पहुंचे नानी, भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद

साउथ सुपरस्टार नानी अपनी आने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज से पहले परिवार संग तिरुपति मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां उनकी सादगी की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म की रिलीज डेट 26 मार्च 2026 से बदलकर अब 21 अगस्त 2026 कर दी गई है।

साउथ के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म से उनका दमदार लुक सामने आया था, जिसे फैन्स ने खूब पसंद किया। अब नानी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करते नजर आ रहे हैं।

परिवार के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में दिखे नानी

नानी अपनी फिल्म की रिलीज से पहले तिरुपति के मशहूर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नानी बिल्कुल सिंपल और ट्रेडिशनल कपड़ों में बेहद शांत अंदाज में मंदिर परिसर में चलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही फैन्स उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और उनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं।

बदल गई 'द पैराडाइज' की रिलीज डेट

नानी की इस तिरुपति यात्रा को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द पैराडाइज' से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म को लेकर फैन्स के बीच पहले से ही काफी क्रेज है। हालांकि, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया है। यह फिल्म पहले 26 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म 21 अगस्त 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

फिल्म की तगड़ी स्टार कास्ट

'द पैराडाइज' एक बड़े स्केल की फिल्म होने वाली है, जिसमें नानी के साथ-साथ इंडस्ट्री के कई शानदार एक्टर्स स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म की स्टार कास्ट में सोनाली कुलकर्णी, राघव जुयाल, कायादु लोहार, मोहन बाबू और ईश्वरी राव जैसे नाम शामिल हैं।

दैनिक राशिफल

मेष कल का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन कल आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता आपको सफलता दिलाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। किसी मित्र से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

कर्क भावनात्मक रूप से संतुलित रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कन्या कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला कल का दिन शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिलेंगे। यात्रा का योग बन सकता है।

वृश्चिक धैर्य और संयम से काम लें। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं।

मकर करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ भाग्यवृद्धि का दिन है। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं।

मीन सावधानीपूर्वक निर्णय लें। अनावश्यक विवादों से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें।

आपातकाल का काला सच लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार और कांग्रेस की ऐतिहासिक जिम्मेदारी

भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक गौरवशाली उपलब्धियों से भरा हुआ है, लेकिन इसी इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी दर्ज है जिसे देश आज भी पीड़ा और चिंता के साथ याद करता है। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर ऐसा प्रहार था जिसने संविधान की मूल भावना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गहरे संकट में डाल दिया। यह वह समय था जब सत्ता को सर्वोपरि मानते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, विपक्ष की आवाज दबाई गई, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और हजारों राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक बताया और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला था। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी और न्याय पाने का अधिकार देता है, लेकिन उस दौर में इन अधिकारों को लगभग समाप्त कर दिया गया। सरकार के विरोध में बोलना अपराध जैसा बन गया था। अखबारों को प्रकाशित होने से पहले सरकारी सेंसर की अनुमति लेनी पड़ती थी। समाचारों को रोका जाता था और सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने के प्रयास हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन उस समय कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिनसे यह संदेश गया कि सरकार न्यायपालिका पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती है। लोकतंत्र में सत्ता के तीनों स्तंभों के बीच संतुलन आवश्यक होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान यह संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। यही कारण है कि आज भी संवैधानिक विशेषज्ञ उस दौर को भारतीय लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा मानते हैं।

आपातकाल का सबसे विवादास्पद और अमानवीय पक्ष जबरन नसबंदी अभियान था। परिवार नियोजन के नाम पर लाखों लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर सबसे अधिक दबाव डाला गया। सरकारी कर्मचारियों को लक्ष्य दिए गए और कई स्थानों पर लोगों को पकड़कर शिविरों में ले जाया गया। अनेक परिवार इस अभियान से प्रभावित हुए और कई लोगों की जान तक चली गई। यह केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं था बल्कि नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का ऐसा उदाहरण था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आज भी आपातकाल की चर्चा होती है तो जबरन नसबंदी का विषय सबसे पहले सामने आता है। इसी प्रकार हजारों विपक्षी नेताओं और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के जेलों में बंद कर दिया गया। अनेक ऐसे लोग थे जिनका अपराध केवल इतना था कि वे सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। लोकतंत्र में असहमति को स्थान मिलता है, लेकिन आपातकाल में असहमति को अपराध बना दिया गया। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अत्यंत चिंताजनक मानी जाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि आपातकाल ने उन अनगिनत नागरिकों के साहस को भी सामने लाया जिन्होंने चुप रहने के बजाय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वास्तव में भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। जेलों में बंद रहने वाले नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का संघर्ष भारतीय लोकतंत्र की अमूल्य विरासत बन गया।

सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस कांग्रेस के शासनकाल में यह सब हुआ, क्या वह इस इतिहास को स्वीकार करने का साहस दिखाती है। कांग्रेस आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व और उनके योगदान का उल्लेख करती है, लेकिन क्या वह आपातकाल के उस काले अध्याय को भी उतनी ही स्पष्टता से स्वीकार करती है जिसने लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचाई थी। इतिहास केवल उपलब्धियों से नहीं बनता, बल्कि गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीख लेने से भी बनता है। यदि किसी राजनीतिक दल को लोकतंत्र में विश्वास है तो उसे अपने अतीत की उन गलतियों पर भी ईमानदारी से आत्ममंथन करना चाहिए जिनसे देश को नुकसान पहुंचा।

यह भी सत्य है कि इतिहास के प्रत्येक नेता के योगदान और निर्णय दोनों का मूल्यांकन होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक कार्यों का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन यदि उसके कार्यकाल में लोकतंत्र पर गंभीर आघात पहुंचा हो तो उसकी आलोचना भी उतनी ही स्पष्टता से होनी चाहिए। लोकतंत्र में व्यक्तिपूजा से अधिक महत्वपूर्ण संविधान और संस्थाओं का सम्मान होता है। इसलिए आपातकाल का स्मरण केवल अतीत को दोहराने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र अनेक संघर्षों और बलिदानों की देन है। आपातकाल की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता बल्कि स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष न्यायपालिका, मजबूत विपक्ष और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से मजबूत होता है। जब इनमें से किसी एक पर भी आघात होता है तो लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है।

25 जून केवल एक तारीख नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान और जनता उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आपातकाल की पीड़ा को भूल जाना इतिहास से सीख न लेने के समान होगा। आने वाली पीढ़ियों को यह जानना आवश्यक है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया और किस प्रकार नागरिक अधिकारों की कीमत समझी गई। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता यही है कि आपातकाल समाप्त हुआ, जनता ने मतदान के माध्यम से अपना निर्णय दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से स्थापित हुई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भारत की लोकतांत्रिक चेतना किसी भी निरंकुश प्रवृत्ति से अधिक मजबूत है। इसलिए आपातकाल का स्मरण केवल राजनीतिक विमर्श नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प भी है।

इतिहास का यह काला अध्याय हमेशा याद दिलाता रहेगा कि संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और किसी भी परिस्थिति में इनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

कांतिलाल मांडोत

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

मातृशक्ति को कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

सीतापुर- लहरपुर जिला जज/अध्यक्ष आशीष जैन के आदेशानुसार एवं आलोक यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सीतापुर के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तकिया में मातृशक्ति के साथ विधिक जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी रहमत अंसारी ने उपस्थित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित, महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रतिषेध, लैंगिक समानता तथा बच्चों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकार मित्र उर्मिला ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विधिक विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक समाधान किया गया। उपस्थित महिलाओं ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को समाज के लिए उपयोगी बताते हुए नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा न्याय तक उनकी सहज पहुंच सुनिश्चित करना रहा।

खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत

मिश्रिख (सीतापुर)। तहसील मिश्रिख क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है।लंबे समय से ओवरलोड चल रहे विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी मिश्रिख से शिकायत की है । ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगा ट्रांसफार्मर वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप क्षमता नहीं रखता, जिससे आए दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। इसके चलते बार-बार फाल्ट होने से ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है।और बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति से ग्रामीणों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है और यह समस्या जनहित से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से विद्युत विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर गांव में अधिक क्षमता वाला नया ट्रांसफार्मर स्थापित कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश होना पड़ सकता है। उपजिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र पर गांव के शुभम पांडेय,जमील अली,राजन सिंह,मनोज कुमार पांडेय,गोकरण प्रसाद,संजय सिंह,छोटेलाल त्रिवेदी, पंकज पांडेय, रमेश, रामप्रकाश सहित दर्जनों लोगों के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।अब देखना ये है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है।

निर्जला एकादशी पर श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर तालाबपुरा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

ललितपुर। निर्जला एकादशी (ग्यारस) के पावन अवसर पर तालाबपुरा स्थित श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगल कामना की। मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। भक्तों ने निर्जला व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना की तथा धर्म लाभ अर्जित किया। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर समिति और स्वयंसेवकों द्वारा विशेष प्रबंध किए गए। दिनभर मंदिर में धार्मिक वातावरण बना रहा और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा।

संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है, इसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है- केशव प्रसाद मौर्य

● आपातकाल जैसे काले अध्याय की पुनरावृत्ति कभी नहीं होने देंगे -उप मुख्यमंत्री

संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्रहित के लिए सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि 25 जून, 1975 की मध्य रात्रि को देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। उस दौरान देशवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित किया गया और असहमति की आवाजों को दबाने का कार्य किया गया। मौर्य ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार, समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने की गारंटी देता है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे देश की जनता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया था, लेकिन आपातकाल के दौरान इसी संविधान का सहारा लेकर जनता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के काले दिनों को देश कभी नहीं भूल सकता। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का त्याग, साहस और समर्पण सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्र सेनानियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1975 में तत्कालीन सरकार ने सत्ता के अहंकार में देश पर आपातकाल लगाया और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रहार किया। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया और हजारों लोकतंत्र समर्थकों को जेलों में बंद किया गया। संविधान हत्या दिवस हमें उस दौर की याद दिलाता है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संविधान की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश में चल रही डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की गरिमा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। आपातकाल जैसे दिन देश और प्रदेश में दोबारा नहीं आने दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में हर युवा के लिए अवसर, हर गरीब के लिए सम्मानजनक जीवन और प्रत्येक नागरिक के लिए विकास की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान की शक्ति से आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। मौर्य ने कहा कि जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हमारा संविधान ही वह शक्ति देता है, जिसके माध्यम से देश का प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर ग्राम प्रधान, नगर निकाय प्रतिनिधि, विधायक और सांसद का चुनाव करता है। लोकतंत्र की यही ताकत भारत को विश्व में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

सम्पर्क सूत्र- बी0एल0 यादव

06 जुलाई 2026 को होगी राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक-सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण

लखनऊः राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक 06 जुलाई 2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, टेहरी कोठी, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में सम्पन्न होगी। यह जानकारी देते हुए सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ने बताया कि उक्त बैठक में परमिटों के नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों, नये परमिटों के आवेदन पत्रों, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-86 के अंतर्गत परमिटों को निरस्त/ निलम्बित करने की कार्यवाही एवं अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। संबंधित व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

सम्पर्क सूत्र- आशीष सिंह

खराब ट्रक से टकराई बुलेट, मामा की मौत; भांजा गंभीर घायल

● निमंत्रण से वापस लौटते समय हुआ हादसा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। बाँदा-बहराइच हाईवे पर बुधवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बुलेट बाइक सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से पीछे से जा भिड़ी। सरेनी थाना क्षेत्र के गाजियापुर गेगासों क्रॉसिंग निवासी सर्वेश मौर्य (40) पुत्र भिखारीलाल मौर्य अपने भांजे आयुष मौर्य (22) पुत्र विजय के साथ बाल्हेमऊ में आयोजित निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। रात करीब साढ़े दस बजे सेमरपहा गांव के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेट बाइक का अगला हिस्सा ट्रक की बॉडी के नीचे तक घुस गया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद

सर्वेश मौर्य को मृत घोषित कर दिया। वहीं आयुष मौर्य को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक सर्वेश मौर्य चार भाइयों में सबसे छोटे थे। वह गेगासों क्रॉसिंग पर बीज भंडार की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। घायल आयुष मौर्य मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है और ननिहाल में रहकर डलमऊ में निजी नौकरी करता है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी शशि मौर्य, पुत्र सात्विक और पुत्री अरुणा का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़े भाई राजेंद्र, विजय बहादुर उर्फ झूरी और राजेश सहित अन्य परिजन सदमे में हैं। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है।

युवा पर्यटन क्लब की गतिविधियों को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए 03 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत

● अब तक 75 जनपदों में 1500 से अधिक युवा पर्यटन क्लबों का गठन- जयवीर सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः युवा पर्यटन क्लब के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए 03 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। युवा पर्यटन क्लब का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पर्यटन राजदूतों के रूप में विकसित करना है। इन पर्यटन क्लबों की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवा पर्यटन क्लबों में विभिन्न स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शामिल किया गया है। अब तक 75 जनपदों में 1500 से अधिक युवा पर्यटन क्लब गठित करते हुए 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा गया है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि युवा पर्यटन क्लबों द्वारा रचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों में पर्यटन के प्रति रूचि जगाने के साथ ही रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित और सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। उ0प्र0 में पर्यटन के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। युवाओं के लिए इस क्षेत्र में कैरियर की असीम संभावनायें हैं। इसी दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग अधिक से अधिक युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पर्यटन सेक्टर में युवा शक्ति के आने से पर्यटन में और तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती मिलेगी।

जयवीर सिंह ने बताया कि उ0प्र0 केवल आस्था का केन्द्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, अध्यात्मिक परम्परा और ज्ञान-विरासत का प्रतिनिधि प्रदेश है। इसलिए पर्यटन विकास को केवल आधारभूत ढ़ाचे तक सीमित न रखकर इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में आस्था स्थलों को सहेजा जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों हस्तशिल्प, पारम्परिक कला, खानपान एवं सेवा सेक्टर को व्यापक अवसर प्राप्त होगा। इसको आगे बढ़ाने में पर्यटन क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। **सम्पर्क सूत्र- केवल**

पटेल नगर प्रीमियर लीग का शुभारंभ, 16 टीमों ने कराया पंजीकरण

बिसवां, सीतापुर। पटेल नगर में आयोजित होने जा रही पटेल नगर प्रीमीयर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। प्रतियोगिता का आयोजन मौसम रस्तोगी एवं मोहम्मद आज़म के नेतृत्व में किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में युवा समाजसेवी कृतिन जायसवाल को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्देश्य क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना तथा खेल भावना को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों में दुष्यंत सिंह इलेवन के कप्तान हर्ष ब्रावो तथा विमल टाइगर इलेवन के कप्तान विमल शामिल हैं। दुष्यंत सिंह इलेवन की टीम में अतुल यादव, दुष्यंत सिंह, आयुष, अर्पित, आदि, शैलेंद्र, अमन और बृजेश जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं विमल टाइगर इलेवन में अंकित, नाग, विशाल, सद्दाम, अभिषेक, आयुष, तन्नू और विभु अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। प्रतियोगिता के दौरान रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद जताई जा रही है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 'छात्रावास निर्माण योजना' के अन्तर्गत 06 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण

●ओ0बी0सी0 छात्र-छात्राओं को शीघ्र ही शैक्षिक आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास निर्माण एवं छात्रावास अनुरक्षण योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता युक्त सुरक्षित, सुविधाजनक एवं अनुकूल शैक्षिक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उ0प्र0 सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 20 करोड़ रूपये के बजट की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं के छात्रावास हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात 90:10 तथा छात्रों के छात्रावास हेतु 60:40 अनुपात निर्धारित किया गया है। इसमें कुल 33 प्रतिशत छात्रावासों का निर्माण छात्राओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक कुल 102 छात्रावासों का निर्माण कराया जा चुका है, जिनमें 59 छात्रों हेतु और 43 छात्राओं के लिए, जिनकी कुल क्षमता 5400 की है। विगत वर्ष 2013 छात्र-छात्राओं द्वारा इसका लाभ उठाया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक में मंत्री जी को बताया गया कि राजकीय पॉलिटेक्निक, हण्डिया (प्रयागराज), राजकीय के.जी.के. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (मुरादाबाद), काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर (संत रविदास नगर), सर्वोदय इंटर कॉलेज, मिहीपुरवा (बहराइच), लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय (गोण्डा), वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (महोबा) में निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज (हमीरपुर) में निर्माण कार्य 90 प्रतिशत, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक (लखनऊ) का निर्माण कार्य 85 प्रतिशत और फैज-ए-आम इंटर कॉलेज (मेरठ) का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, जिसको जुलाई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कश्यप ने बताया कि उ0प्र0 सरकार ने पूर्व में निर्मित छात्रावासों के रख-रखाव एवं मरम्मत की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 'छात्रावास अनुरक्षण योजना' वर्ष 2023-24 से आरम्भ की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 05 करोड़ रूपये बजट का प्राविधान किया गया है। उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी निर्माण और अनुरक्षण कार्यों की निरंतर और नियमित मॉनीटरिंग करें साथ ही निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य गुणवत्ता व मानक के अनुरूप पूर्ण कराने को सुनिश्चित करें ताकि छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निर्माण व अनुरक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा छात्रावास संबंधी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

सम्पर्क सूत्र- मो0 इकबाल खॉ

अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

● जुलाई माह में जांच कर कार्रवाई करने व प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश

बस अड्डों, प्रमुख मार्गों, टोल प्लाजा, जनपद सीमाओं तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर सघन जांच किया जाए-दयाशंकर सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरिज बसों एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज बसों में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता एवं जिम्मेदारी भी है। हाल ही में लखनऊ में एक चार मंजिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने की गंभीर घटना घटित होने के उपरान्त स्पष्ट है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशीलता जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि यात्री वाहनों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में वाहनों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना की स्थिति में प्रारम्भिक स्तर पर आग पर नियंत्रण स्थापित कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-128 के उपनियम (13) (3) के अनुसार प्रत्येक पर्यटक यान अग्निशमन यंत्र (जो ड्राई पाउडर टाइप हो और इंजन कक्ष के पास लगा हो) से सुसज्जित होना आवश्यक है। परिवहन मंत्री ने स्कूल बसों की विशेष जांच करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 जुलाई से सभी शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल बसों के संचालन हेतु निर्गत सुरक्षा मानकों के अन्तर्गत भी अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता अपेक्षित है। परिवहन मंत्री ने जुलाई माह में संपूर्ण प्रदेश में व्यापक अभियान चला कर जांच की कार्रवाई करने एवं प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समस्त स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरिज बसों एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज बसों की मोटर वाहन निरीक्षक/एटीएस सेन्टर द्वारा फिटनेस जाँच के समय अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता, क्षमता, वैधता, कार्यशीलता एवं वाहन में उसके उचित स्थान पर स्थापित होने का विशेष रूप से परीक्षण किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि अग्निशमन यंत्र निर्धारित अवधि के भीतर रिफिल/सर्विस किया गया हो तथा उस पर अंकित वैधता अवधि समाप्त न हुई हो। जिन वाहनों में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध न हो अथवा अग्निशमन यंत्र कार्यशील अवस्था में न पाया जाये अथवा उसकी वैधता समाप्त हो चुकी हो, ऐसे वाहनों की कमियों के निराकरण तक फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्गत न किया जाये तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये। परिवहन मंत्री ने समस्त प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर बस अड्डों, प्रमुख मार्गों, टोल प्लाजा, जनपद सीमाओं तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर उपरोक्त श्रेणी के वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान अग्निशमन यंत्र न पाये जाने अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विशेष रूप से स्लीपर बसों की जांच करते समय आपातकालीन निकास, हैमर, अग्निशमन यंत्र, विद्युत वायरिंग एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जाये। स्कूल बसों की जांच के दौरान अग्निशमन यंत्र के अतिरिक्त सुरक्षा मानकों के अनुपालन का भी सत्यापन किया जाये, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों, बस संचालकों, यूनियन पदाधिकारियों, परिवहन कम्पनियों एवं विद्यालय प्रबन्धनों को अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरुक करते हुए अग्निशमन यंत्रों के नियमित अनुरक्षण एवं समयबद्ध परीक्षण हेतु निर्देशित किया जाये। परिवहन आयुक्त श्री आशुतोष निरंजन ने परिवहन मंत्री के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश को प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण उनकी ईमेल-जबमण्नच/दपबण्पद पर उपलब्ध कराएं।

सम्पर्क सूत्र-आशीष सिंह

गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, एसी मैकेनिक गंभीर रूप से घायल

लालगंज (रायबरेली)। गंगा एक्सप्रेसवे पर मेरुई गांव के निकट बुधवार देर शाम एक बाइक सवार एसी मैकेनिक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे यूपीडा की एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।अयोध्या जनपद के इनायत नगर क्षेत्र के बारून बाजार निवासी मोहम्मद अमजद गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन ट्रांजिट रेस्ट हाउस के शौचालय में एसी लगाने का कार्य कर रहे थे। बुधवार शाम वह बाइक से किसी काम से निकले थे। मेरुई गांव के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से टकरा गई। इससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इसके कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सीएचसी की इमरजेंसी में तैनात डॉ. गौरव पांडे ने बताया कि घायल की हालत नाजुक थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव; मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

● आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर मे काटा हंगामा,पुलिस से नोकझोंक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के सोहाईबाग मजरे आलमपुर मोहल्ले में गुरुवार को एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार शिवानी (27) पत्नी वरुण आर्या का शव कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। बताया जा रहा है कि घटना के समय पति और परिवार के अन्य सदस्य नीचे मौजूद थे। कुछ देर बाद जब पति वरुण ऊपर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया,

जहां शिवानी फंदे से लटकी मिली। परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और मृतका के परिजनों के बीच नोकझोंक भी हुई। बताया गया कि शिवानी की शादी 1 दिसंबर 2025 को हुई थी और अभी विवाह को छह माह ही हुए थे। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने आक्रोशित परिजनों को समझाकर शांत कराया।बताया कि पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ अग्निकांड के मृत छात्रों की स्मृति में बिसवां में कैंडिल मार्च

बिसवां (सीतापुर)। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड में मृत छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार शाम पत्थर शिवाला परिसर से कैंडिल मार्च निकाला गया। इससे पूर्व आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मार्च में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों ने भाग लेकर हादसे पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान कैथी टोला निवासी छात्र आदित्य श्रीवास्तव को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनकी अग्निकांड में मृत्यु हो गई थी। उपस्थित लोगों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

जनसुनवाई में मंत्री ए.के. शर्मा ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

● बिजली, पानी, सफाई, सीवर और आवास संबंधी मामलों पर मंत्री

ए.के. शर्मा सख्त, समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग से संबंधित मामलों की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे। इनमें नगर निकायों की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सीवर एवं जल निकासी की समस्याएं, विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं क्षमता वृद्धि, विद्युत आपूर्ति से जुड़े प्रकरण, आवास योजनाओं के लाभ, सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न जनसुविधाओं से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल रहीं। मंत्री शर्मा ने एक-एक प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने तथा शिकायतकर्ताओं को यथाशीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनसुनवाई केवल शिकायत सुनने का माध्यम नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच सीधे संवाद तथा विश्वास को मजबूत करने का प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के

समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत आपूर्ति, नए कनेक्शन, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि तथा अन्य तकनीकी मामलों से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

वहीं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को सफाई, पेयजल, सीवर, जलभराव, आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सम्पर्क सूत्र- प्रवीण मालवीय

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली में कोचिंग सेंटरों पर कंट्रोल की तैयारी, सरकार 3 महीने में लाएगी नया कानून

नई दिल्ली। राजधानी में संचालित कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के सभी 924 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कराया जाएगा। जिन संस्थानों को पहले सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नोटिस दिया जा चुका है और फिर भी वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सील कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिन कोचिंग सेंटरों में पहली बार अनियमितताएं मिलेंगी, उन्हें नोटिस जारी कर एक महीने का समय दिया जाएगा ताकि वे कमियां दूर कर सकें। यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने कोचिंग सेंटरों के नियमन को लेकर गठित जस्टिस गौबा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों के आधार पर उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो कोचिंग संस्थानों के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के मानकों का परीक्षण करेगी। सरकार अगले तीन माह के भीतर कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित कानून का मसौदा सार्वजनिक करेगी। इस कानून में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता, संचालन संबंधी मानक और भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण जैसे प्रधान शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि निरीक्षण अभियान की नोडल एजेंसी दिल्ली नगर निगम होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर नियमों के तहत कोचिंग सेंटर संचालित करने की अनुमति नहीं है, वहां चल रहे संस्थानों को किसी भी स्थिति में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली: डीडीए के खुले नाले में गिरने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली। नरेला इलाके में डीडीए के एक खुले गंदे नाले में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त 36 साल के सूरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है शुक्रवार सुबह में सैर करने वाले लोगों ने नाले में बेसुध व्यक्ति देख पुलिस को घटना की जानकारी दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बेसुध व्यक्ति को नाले से निकाला और उसे पास के अस्पताल लेकर गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि युवक नाले तक कैसे पहुंचा और वहां गिरा या गिराया गया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का पता चलेगा, उसके बाद ही इस बाबत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि सुबह 6.30 बजे नरेला थाना पुलिस को सेक्टर पांच नरेला के पास नाले में एक युवक के पड़े होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि सड़क किनारे बने चार से पांच फीट गहरे नाले में एक युवक गिरा हुआ है। नाला गंदगी से अटा-पटा था और बाद में युवक को बाहर निकाला गया। वह अचेत अवस्था में था। पुलिस उसे पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके भाई धीरू से हुई पूछताछ में पता चला कि मृतक अविवाहित था और ढोल बजाने का काम करता था। वह नशे का आदी भी था। वह बराबर दो तीन दिन तक घर से बाहर रहता था। बृहस्पतिवार रात में घर से बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। बाहर रहने की वजह से उनलोगों ने रात में उसकी तलाश नहीं की। लेकिन सुबह में उन्हें घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने बताया जिस नाले में गिरने से युवक की मौत हुई है, वह सड़क से दूर है। सड़क के बगल में फुटपाथ है और नाला से सटी दुकानें हैं। इस नाले को दुकान वालों ने ढक रखा है, हालांकि कई अन्य जगहों पर वह खुला हुआ है। जिस जगह पर युवक नाले में गिरा वहां शहजाद सैलून है। शहजाद ने बताया कि वह रात दस बजे अपनी दुकान बंद कर वहां से गया था। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने आशंका जताई कि घटना देर रात की है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि युवक नशे में होने की वजह से वहां पहुंचा होगा, या किसी ने उसकी हत्या कर उसे नाले में फेंक दिया होगा। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है और अब पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुटी हुई है।

ईरान ने सीजफायर का किया उल्लंघन

● ईरान के उप-विदेश मंत्री का कहना है कि होर्मुज से 'समांतर रास्तों' के जरिए सुरक्षित गुजरने की गारंटी नहीं दी जा सकती. ईरानी विदेश मंत्रालय ने US-GCC के बयान की आलोचना की और कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से असुरक्षा बढ़ती है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज जानकारी दी कि ईरान ने सीजफायर तोड़ दिया है. उसने होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ड्रोन अटैक कर दिया. जवाबी कार्रवाई में अमेरिका सेना ने भी पलटवार किया और ईरान के तीन ड्रोन मार गिराए. ट्रंप ने ईरान की इस कार्रवाई को मूर्खतापूर्ण बताया है।

'सीजफायर समझौते का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन'

ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे जहाजों पर कम से कम चार 'वन-वे अटैक ड्रोन' दागे. इनमें से एक ड्रोन ने सामान ढोने वाले एक बड़े और बहुत महंगे जहाज के ऊपरी डेक पर जोरदार टक्कर मारी. इससे नुकसान तो हुआ, लेकिन जहाज अपना सफर जारी रखने में कामयाब रहा. हमने तीन अन्य ड्रोन मार गिराए. जाहिर है, यह हमारे सीजफायर समझौते का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन है। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट में जहाज या हमले के समय की पहचान नहीं बताई गई. साथ ही ट्रंप ने समझौते के खतरे को लेकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन बृहस्पतिवार को ब्रिटिश सेना ने कहा कि ओमान के तट पर एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के लिए एक नाजुक समय पर हुआ है, क्योंकि वे युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण को लेकर इस क्षेत्र और अमेरिका को लगातार चुनौती दी है, यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिका के साथ हुए मौजूदा अंतरिम समझौते के बावजूद भी।

ईरान ने फिर दिखाए तेवर

वहीं अल जजीरा के अनुसार, ईरान के उप-विदेश मंत्री का कहना है कि होर्मुज से 'समांतर रास्तों' के जरिए सुरक्षित गुजरने की गारंटी नहीं दी जा सकती. ईरानी विदेश मंत्रालय ने US-GCC के बयान की आलोचना की और कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से असुरक्षा बढ़ती है। अमेरिका ईरान अभी भी अंतरिम शांति समझौते की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मुख्य जलडमरूमध्य से जहाज़ों को गुजारने और ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार के भविष्य से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. अंतरिम समझौते के तहत, दोनों पक्षों के पास विवरण तय करने के लिए 60 दिन का समय है।

दुबई में मिसाइल अलर्ट से हड़कंप

शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात में तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल की चेतावनी ने क्षेत्र में जारी तनाव को और उजागर कर दिया, जो पिछले कुछ दिनों में कार्गो जहाज पर हमले और लेबनान में इजरायली हमलों के बाद हुआ था. मोबाइल फोन पर आए इस अलर्ट ने दुबई शहर-राज्य में कई लोगों को चौंका दिया; अंतरिम युद्धविराम के बाद से यह इस तरह का पहला अलर्ट था। अलर्ट के कुछ समय बाद, अमीराती अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच फोन पर बातचीत हुई. इसमें शेख अब्दुल्ला के हवाले से कहा गया कि UAE ने ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते के प्रति 'पूरी प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया.' इसमें कहा गया, 'गंभीर कूटनीति और जिम्मेदार बातचीत ही सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकटों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। '

दिल्ली कांग्रेस ने की संगठन को मजबूत करने की तैयारी, 70 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए 509 मंडलम अध्यक्ष

● दिल्ली कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 509 मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति की है। यह कदम पार्टी के बूथ स्तरीय नेटवर्क को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। पार्टी के बूथ स्तरीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 509 मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होती हैं और इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को 'मजबूत और सक्रिय' करना है। पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार 509 मंडल अध्यक्षों को दिल्ली की सभी जिला इकाइयों और विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया गया है। बकौल यादव, नवनियुक्त पदाधिकारियों से कांग्रेस की विचारधारा और संगठनात्मक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने, अपने-अपने मंडलों (इकाइयों) में पार्टी को मजबूत करने, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखने और पार्टी द्वारा समय-समय पर जारी कार्यक्रमों और अभियानों को लागू करने का आग्रह किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ये नियुक्तियां दिल्ली कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के मद्देनजर बूथ-स्तरीय तंत्र को मजबूत करने का अभियान शुरू करने के कुछ सप्ताह बाद हुई हैं।

कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की गई

इस महीने की शुरुआत में, पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए)-1 कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की और कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान किसी भी योग्य मतदाता, विशेष रूप से दलित, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से, को मतदाता सूची से न हटाया जाए।

रेलवे स्टेशनों और रेलवे लाइनों से मोबाइल फ़ोन चुराने वाले एक आदतन चोर 07 चोरी के मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- स्वपन शर्मा IPS, माननीय पुलिस कमिश्नर, लुधियाना, समीर वर्मा PPS. एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, ज़ोन-1 लुधियाना और अनिल कुमार भनोट PPS, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, सेंट्रल लुधियाना के निर्देशों पर, इंस्पेक्टर परमवीर सिंह, चीफ़ ऑफ़िसर ऑफ़िसर ऑफ़ पुलिस स्टेशन डिवीज़न नंबर-01 लुधियाना की टीम ने इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह (RPF) और उनकी टीम के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों और आस-पास के इलाकों में मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इसी बीच, 22.06.2026 को, शिव कुमार उर्फ़ शिबू पुत्र मंजीत कुमार, निवासी हाउस नंबर 1101/2, गली नंबर 11, मोहल्ला राम नगर, 33 फुटा रोड, जमालपुर, लुधियाना को 04 चोरी के मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी रेलवे स्टेशन लुधियाना, रेलवे लाइन और घंटा घर इलाके में मोबाइल चोरी की कई वारदातें करता है। इस बारे में थाना डिवीजन नंबर-01 लुधियाना में केस नंबर 97 तारीख 22.06.2026 को दर्ज करके जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी का दो दिन का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर 24.06.2026 को अलग-अलग कंपनियों के 03 और चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए।

इस तरह कुल 07 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज हैं।

योग व स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान पर दो प्रशिक्षक सम्मानित

देवरिया। योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य करने पर योग प्रशिक्षक पिंटू लाल यादव और जितेंद्र दीक्षित को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि समाजहित में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर जनसेवा से जुड़ें। समारोह में विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, मंडल अध्यक्ष दिवाकर चंद यादव, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. जयराम यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने दोनों सम्मानित प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यों की सराहना की।

पिछड़े वर्ग के लोगों तक सरकारी भलाई की योजनाओं का पूरा फ़ायदा पहुँचाएँ: मलकीत थिंड

● पंजाब स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन ने लुधियाना के बचत भवन में अलग-अलग सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- पंजाब स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन श्री मलकीत थिंड ने गुरुवार को लोकल बचत भवन में अलग-अलग सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग का मुख्य मकसद BC (पिछड़े वर्ग) समुदाय के लोगों की सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही भलाई की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर असरदार तरीके से लागू करने का रिव्यू करना था। मीटिंग के दौरान, चेयरमैन मलकीत थिंड ने साफ़ शब्दों में कहा कि सरकार की भलाई की योजनाओं का असली मकसद तभी पूरा होता है जब उनका फ़ायदा हर योग्य व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि BC कैटेगरी के लोगों को सरकारी योजनाओं का सही और समय पर फ़ायदा मिले। चेयरमैन ने अलग-अलग डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक सरकारी स्कीमों के तहत दिए गए फायदों के बारे में डिटेल में जानकारी ली और आंकड़ों के आधार पर उनका रिव्यू किया। इस दौरान, उन्होंने कई जगहों पर सामने आई कमियों को तुरंत दूर करने के लिए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए। मीटिंग के दौरान, चेयरमैन मलकीत थिंड ने BC समाज के लोगों और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सीधी बातचीत भी की। उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को ध्यान से सुना।

कई मामलों का मौके पर ही हल किया गया, जबकि बाकी मामलों को तय समय में हल करने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जरूरी गाइडलाइंस जारी की गईं। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वेलफेयर स्कीमों की जानकारी गांवों और शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर फैलाई जानी चाहिए ताकि BC समाज का हर वर्ग इन स्कीमों के बारे में जान सके और बिना किसी सरकारी परेशानी के फायदा उठा सके। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर फील्ड ऑफिसर लुधियाना तुशिता गुलाटी ने भरोसा दिलाया कि कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से सभी वेलफेयर स्कीमों को असरदार तरीके से लागू किया जाएगा। इस मीटिंग में मार्केट कमेटी साहनेवाल के चेयरमैन हेमराज राजी, चीफ मिनिस्टर फील्ड ऑफिसर लुधियाना तुशिता गुलाटी, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर प्रदीप कुमार, डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर हरपाल सिंह गिल के अलावा सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सोशल सर्विस ऑर्गनाइज़ेशन के मेंबर और बड़ी संख्या में BC सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए।

क्या गौतम गंभीर की रणनीति हो गई फेल? आयरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार पर श्रेयस अय्यर ने तोड़ी चुप्पी

● भारत को आयरलैंड के खिलाफ 34 रन से हार का सामना करना पड़ा है. हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने चुप्पी तोड़ी है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भारत को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा. पहली बार आयरलैंड ने भारत को हराया है. भारत को मिली ऐसी शर्मनाक हार के बाद कप्तानी में डेब्यू कर रहे श्रेयस अय्यर ने हार का कारण गेंदबाजों को बताया है, हार के बाद अय्यर ने कहा 'मुझे लगता है कि शुरुआत में गेंदबाज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें मूवमेंट मिल रहा था और कुछ विकेट भी मिले. तो हमें शानदार शुरुआत मिली, लेकिन बीच में हम अपनी योजना पर ठीक से अमल नहीं कर पाए. हमने उन्हें सीधे ग्राउंड की तरफ शॉट खेलने दिए, जहां हमें पता है कि बाउंड्री छोटी है. लेकिन फिर, जब हमें ओवर रोकने थे, तब गेंदबाजों ने शानदार काम किया. तो मुझे लगा कि जिस तरह की शुरुआत मिली थी, उसे देखते हुए 140 का स्कोर चेज करने के लिए ज़बरदस्त होता. फिर भी, यहां का अनुभव बहुत अच्छा रहा. हमें इन हालात में खेलने का मौका मिला, पिच के बारे में अच्छी जानकारी मिली, और हां, कप्तान के तौर पर यह एक बढ़िया शुरुआत थी '।

जो हुआ हम उसे भूल जाएंगे

श्रेयस अय्यर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, 'जो हुआ उसे हम भूल जाएंगे, इस मैच से निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम कोशिश करेंगे कि अगले मैच में पूरी ताकत के साथ उतरें, शुरुआत में उन्हें मदद मिल रही थी, और शिवम ने पहले भी अहम ओवर डाले हैं. इसलिए मैं हमेशा उन पर भरोसा करता हूं, और मैंने उनके साथ घरेलू क्रिकेट में भी खेला है. मैं उनकी ताकत और कमजोरियों को जानता हूं। और हर्षित राणा ने जबरदस्त बॉलिंग की. चोट से उबरकर इस स्तर पर खेलना और ऐसा टैलेंट दिखाना, वाकई शानदार है।

अगले मैच का है बेसब्री से इंतजार

भारतीय कप्तान ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, आप बस मैदान पर जाकर मैच नहीं जीत सकते. आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें. जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको वर्तमान में रहना होगा और अगर विरोधी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिले, तो उसका फायदा उठाना होगा. और हा, किसी भी पल या स्थिति को कभी हल्के में न लें. अगले मैच का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 182 रन बनाए थे जिसके बाद भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 पर आउट हो गई. आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया.।

अब जस्टिस स्वर्ण कांता नहीं सुनेंगी सांसद-विधायकों से जुड़े केस

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के रूटीन रोस्टर बदलाव के बाद अब एक जुलाई से न्यायमूर्ति मनोज कुमार जैन सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे। अब तक ये रोस्टर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के पास था और एमपी-एमएलए रोस्टर पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। अब न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा सिविल रिट से जुड़े मामले की सुनवाई करेंगी। उन्होंने आबकारी घोटाला सहित कई हाई-प्रोफाइल मामलों को देखा। हालांकि, इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य सभी को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ के समक्ष कार्यवाही का अरविंद केजरीवाल ने बहिष्कार कर दिया था।

केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही

इस प्रक्रम की काफी चर्चा रही और न्यायमूर्ति शर्मा ने आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की। मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद आबकारी घोटाला व केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला अन्य पीठ को सौंप दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट का रोस्टर आम तौर पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद बदला जाता है। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने व सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक विशेष एमपी-एमएलए रोस्टर बनाया गया है। यह रोस्टर हाई कोर्ट को सौंपे गए कई तरह के आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है और इनमें मौजूदा और पूर्व सांसद और विधायक शामिल होते हैं।

पुलिस कर्मियों की शिकायतें अब थाने में ही होंगी दूर, शुरू हुई 'डोरस्टेप' व्यवस्था

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मध्य जिला पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब वेतन, पेंशन, मेडिकल रीइम्बर्समेंट, अवकाश, जांच से जुड़े बिल, अकाउंट्स और अन्य प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासनिक और लेखा शाखा के अधिकारी स्वयं हर पखवाड़े पुलिस थानों और यूनिटों में पहुंचकर शिकायतों का समाधान करेंगे। मध्य जिले के उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, जिले में 'डोरस्टेप' (मौके पर जाकर समाधान) शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत प्रशासन और अकाउंट्स शाखा के अधिकारी तय रोस्टर के अनुसार जिले के सभी पुलिस स्टेशनों और यूनिटों का नियमित दौरा करेंगे। दौरे के दौरान कर्मचारियों की शिकायतें मौके पर सुनकर उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा।

प्रत्य दौरे का रिकॉर्ड डेली डायरी में दर्ज होगा

इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए इंस्पेक्टर (एडमिन) और अकाउंटेंट विस्तृत विजिट रोस्टर तैयार करेंगे, ताकि किसी भी पुलिस स्टेशन या यूनिट का दौरा छूट न जाए। प्रत्येक दौरे का रिकॉर्ड डेली डायरी (डीडी) में दर्ज किया जाएगा। इसमें प्राप्त शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई और उनके निस्तारण का पूरा विवरण रहेगा। शिकायतों के समयबद्ध समाधान की निगरानी के लिए साप्ताहिक और पखवाड़ा समीक्षा प्रणाली भी लागू की गई है। एसीपी/मुख्यालय के माध्यम से हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट अतिरिक्त उपायुक्त-द्वितीय को भेजी जाएगी, जबकि प्रत्येक पखवाड़े की अनुपालन रिपोर्ट उपायुक्त के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन से प्रत्येक नगर पंचायत में की जा रही है जनसुनवाई

बाराबंकी। योगी सरकार के निर्देश तथा नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के मार्गदर्शन से संभव के तहत प्रत्येक नगर पंचायत में जनसुनवाई की जा रही है ईसी के तहत रामसनेहीं घाट के अधिशासी अभियंता संतोष चौधरी ने दिव्यांग दंपति की मदद की। पत्नी कमला देवी उम्र 62 वर्ष तथा पंछी लक्ष्मी नारायण उम्र 65 वर्ष जो कि बाराबंकी के नगर पंचायत रामसनेहीघाट चंदौली के निवासी हैं इनका वृद्धा पेंशन बनवाने में मदद की। और स्थानीय निवासियों के समस्या को देखते हुए निस्तारण करने का पूरा विश्वास दिलाया।

अलका याग्निक की बेटी हैं पॉवरफुल बिजनेस वुमन, टैलेंट में नहीं मां से कम

● अलका याग्निक की बेटी सायशा कपूर फिल्मी दुनिया से दूर बिजनेस में सफल हैं, जबकि उनके पति और भाई भी हमेशा चर्चा से दूर रहे. आज हम आपको सायशा की फोटो दिखाने जा रहे हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अलका याग्निक भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपने करियर में हजारों गानों को अपनी आवाज देकर कई पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बनाया है. हाल ही में उन्हें पद्म सम्मान से नवाजा गया, जिसके बाद एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी चर्चा में आ गई. इससे पहले उन्होंने यह भी बताया था कि वह पिछले दो वर्षों से एक दुर्लभ सुनने संबंधी बीमारी से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से लाइमलाइट से दूर रहीं. अब फैंस उनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि उनके पति कौन हैं, बेटी क्या करती हैं और उनके भाई को इंडस्ट्री में कितनी पहचान मिली.

कौन हैं अलका याग्निक के पति?

अलका याग्निक ने साल 1989 में शिलॉन्ग के बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की थी. नीरज का फिल्म या म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं रहा. अलका ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा, इसलिए उनके पति भी सार्वजनिक कार्यक्रमों और लाइमलाइट में कम ही नजर आए। बताया जाता है कि शादी के बाद नीरज ने मुंबई में कारोबार जमाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने शिलॉन्ग लौटकर अपना बिजनेस संभाला. वहीं अलका ने मुंबई में रहकर अपने सिंगिंग करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. अलग-अलग शहरों में रहने के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया।

क्या करती हैं अलका याग्निक की बेटी?

अलका और नीरज की एक बेटी हैं, जिनका नाम सायशा कपूर है. सायशा ने अपनी मां की तरह मनोरंजन जगत में करियर नहीं चुना. वह बिजनेस की दुनिया में सक्रिय हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. उन्होंने हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग में एमबीए किया है और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट व सेल्स के क्षेत्र में काम किया

है। जानकारी के अनुसार, वह 'Raincheck Earth' से जुड़ी रही हैं, जो चेरापूंजी क्राफ्ट जिन के कारोबार से संबंधित है. इसके अलावा वह मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट Boveda Bistro की को-ओनर भी बताई जाती हैं. निजी जीवन में सायशा ने 2017 में बिजनेसमैन अमित देसाई से सगाई की और 2018 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए।

भाई भी बने सिंगर, लेकिन नहीं मिली बहन जैसी सफलता

अलका याग्निक को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला. उनके पिता धर्मेंद्र शंकर भारतीय नौसेना में अधिकारी थे, जबकि उनकी मां शुभा याग्निक शास्त्रीय गायिका थीं. महज छह साल की उम्र में अलका ने कोलकाता आकाशवाणी के लिए गाना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र में मुंबई आ गई. इसके बाद उनका करियर लगातार आगे बढ़ता गया।